POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पूरे हिन्दुस्तान में वर्ष 1952 में पहली बार जनता ने अपना वोट देकर सरकारों को चुना था। तब से हम देश में लोकतंत्र की परवरिश कर उसे सुदृढ़ बनाने के प्रयासों में लगे हैं। लेकिन इतने सालों के बाद भी चुनाव सुधारों की दिशा में कोई खास उपलब्धि नजर नहीं आ पा रही।

मेरा मानना है कि यदि हमारी चुनाव प्रणाली दोष रहित हो जाए तो बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। चुनाव सुधार से ही देश में राजनीतिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

पिछले कुछ सालों से हम नवाचारों और सुधारों की दिशा में बढ़ते नजर तो आने लगे हैं, लेकिन अभी उनके प्रत्यक्ष नतीजे सामने आने बाकी हैं। मसलन, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दे में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से नोटबन्दी और बेनामी सम्पत्ति जब्त करने, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने जैसे लिए गए फैसले गिनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसे महज एक शुरुआत माना जा रहा है।

देश में चुनावों के वक्त पर जनता की खासतौर पर मांग यह होती है कि चुनाव धन और बल से मुक्त होने चाहिए। राजनीतिक दल अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को चुनाव में खड़ा नहीं करें। चुनाव में जातिवाद और वंशवाद को भी बढ़ावा नहीं दिया जाए। जीतने पर सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा-पत्रों को पूरी तरह अमल में लाया जाए।

अगर राजनीतिक दल यह सब ठान लें और चुनाव आयोग को सशक्त बना दिया जाए तो देश तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा और इससे देश की जनता का लोकतंत्र के प्रति सही मायने में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल जनता की इस मंशा पर खरे उतरने को तैयार होंगे?

पुराने स्टॉक पर नई कीमत नहीं लिखी तो हो सकती है जेल

जीएसटी के बाद पुराने स्टॉक पर नई कीमत नहीं लिखने वाले निर्माताओं को जेल की सजा भी हो सकती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि संशोधित एमआरपी लिखना जरूरी है, वर्ना पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना, दूसरी बार 50 हजार रुपए, उसके बाद हर गलती पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा एक साल तक की जेल भी हो सकती है।

सरकार ने कंपनियों के पुराने स्टॉक को नए प्रिंट के साथ सितंबर माह तक बेचने की इजाजत दी है। कीमत को लेकर लोगों से जो शिकायतें मिल रही हैं,उन्हें दूर करने के लिए मंत्रालय ने एक समिति बनाई है। हेल्पलाइन की संख्या भी 14 से बढ़ाकर 60 की गई है। पासवान ने कहा कि जीएसटी लागू करने में शुरुआती दिक्कतें हैं, इन्हें जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा।

प्रोडक्ट पर नई के साथ पुरानी कीमत भी रहेगी, ताकि ग्राहक को पता चल सके कि दाम में कितना अंतर आया है। उन्होंने बताया कि उत्पादकों को पैकेज्ड फूड पर बनाने, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, मात्रा और सावधानी संबंधी पांच सूचनाएं बड़े आकार में छापना जरूरी है। इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स में संशोधन किए गए हैं।

बिजली कनेक्शन नहीं काटा, डिस्कॉम पर डेढ़ लाख का हर्जाना

जयपुर जिले की कोटपूतली में जले सिंह की मां के नाम से एक कृषि कनेक्शन था। उन्होंने कनेक्शन कटवाने के लिए जयपुर डिस्कॉम में प्रार्थना-पत्र दाखिल किया। लेकिन उनका कृषि कनेक्शन नहीं काटा गया। उन्होंने कई बार जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों व जयपुर विद्युत वितरण निगम, कोटपूतली कार्यालय में जाकर कनेक्शन काटने के लिए निवेदन भी किया, लेकिन उनके प्रार्थना-पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हारकर उन्होंने उपभोक्ता मंच जयपुर तृतीय में जयपुर डिस्कॉम एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम, कोटपूतली के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने मंच को सभी स्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि इस बीच उनके बिजली कनेक्शन का दुरुपयोग भी किया गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने जयपुर डिस्कॉम व जयपुर विद्युत वितरण निगम, कोटपूतली को सेवा का दोषी मानते हुए डेढ़ लाख रुपए का हर्जाना लगाया। मंच ने यह भी आदेश दिया कि हर्जाना राशि की वसूली जयपुर डिस्कॉम के एसई और जयपुर विद्युत वितरण निगम, कोटपूतली के एईएन और अधिशासी अभियंता के वेतन से की जाए। मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के सीएमडी को तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

मोटर वाहन विधेयक पर चर्चा

जरा सी चूक, चिन्दगी भर का दर्द!

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 पर जागरूकता के लिए 'कट्स' एवं ऑक्सफोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की ओर से कोटा में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार सिंघल, सहायक कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों को जागृत करना जरूरी है। सभी लोग यदि सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने विधेयक की खासियतों एवं भारत के सड़क सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में राज्य सरकार के विधिक सलाहकार भुवनेश शर्मा ने विधेयक की जानकारी देते हुए कहा कि कानून समाज की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उनकी पालना आवश्यक है। विधिक विभाग के एडवोकेट परमेश्वर दाधीच ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि जरा सी चूक हो जाए तो जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में भी सड़क सुरक्षा से जुड़े कई संभागियों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन ऑक्सफोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कोटा के अनवर अहमद खान ने किया।

जीएसटी से आर्थिक सुधार की शुरुआत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि जीएसटी देश-प्रदेश की उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा। यह आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस निर्णय के बाद माल और सेवाओं पर देशभर के करों में समानता आ जाएगी। इससे व्यापार करना आसान होने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करने से पहले केन्द्र सरकार ने आम आदमी का विशेष ध्यान रखा है। अनाज को कर मुक्त व दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुओं पर टैक्स मौजूदा कर भार से कम रखा गया है। जीएसटी लागू करने से पहले प्रदेश में भी इसकी पूरी तैयारी की गई थी।

किसान खुदकुशी का मुआवजा हल नहीं

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि किसान की आत्महत्या के बाद मुआवजा देना समस्या का हल नहीं है। सरकार को किसानों के कर्ज के असर को कम करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके सही क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करें। फसल बर्बाद होने पर किसानों से ऋण वसूली में नरमी बरती जाए।

जनहित याचिका की सुनवाई पर चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच ने सरकार को उक्त निर्देश दिए। बैंच ने सरकार की इस बात पर भी सहमति जताई कि किसान कल्याण योजनाओं के नतीजे सामने आने के लिए एक साल का वक्त दिया जाए।

घट रही है भूमि की उर्वरा शक्ति

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण की रिपोर्ट एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने राजस्थान की समस्त जमीन का लैंडसेट इमेजरी के जरिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

यह सर्वे सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। इसमें सामने आया है कि मिट्टी के पोषक तत्वों में लगातार कमी आ रही है। रासायनिक खाद-बीज के अंधाधुंध उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेतरतीब रासायनिक खाद और बीजों के उपयोग को रोका जाए। मिट्टी की जांच के बाद ही आवश्यक समुचित मात्रा में उर्वरकों को उपयोग में लिया जाए।

ई-पंचायत पर अभी भी कछुआ चाल

पंचायतीराज इकाईयों में हर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में ई-पंचायत वेब एप्लीकेशन से जोड़ने का मामला अभी भी राजनीतिक दबाव में नजर आ रहा है।

राज्य सरकार ने सरपंचों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में पारदर्शिता के इस कदम को सितम्बर-अक्टूबर महीने तक आगे सरका दिया है। इससे पहले होने वाली तैयारियां भी कछुआ चाल से आगे बढ़ रही हैं।

ई-पंचायत वेब एप्लीकेशन से जोड़ने पर टेंडर और खर्च के हिसाब में पारदर्शिता होने से ज्यादातर भ्रष्ट जनप्रतिनिधि घबराए हुए हैं। इससे कमीशन और घपले की गुंजाइश कम होने से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है।

सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना शुरू

प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना शुरू की गई है। दिसम्बर 2013 तक कृषि कनेक्शन के लिए लम्बित 3 और 5 एचपी के लगभग 70 हजार आवेदकों के कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने व ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। इस योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और बिजली बिल भी नहीं देना पड़ेगा। योजना में पंजीकरण की जानकारी विद्युत निगम के संबंधित अभियंता (पवस) कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मोदी की नजर बच्चों के टीकों पर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अगले साल के अंत तक 90 फीसदी बच्चों को सभी टीके लगने लगें।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों की विशेष कोशिशों के बाद भी अभी तक देश में टीकाकरण का कवरेज 72 फीसदी तक ही पहुंचा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान इसकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें भेजी जाए।

प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार से असंतोष जताते हुए इस पर खासतौर पर ध्यान देने को कहा है। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारत टीकाकरण में फिसड्डी होने का अपना एक बड़ा कलंक धो सकेगा।

पौधे लगाकर लाएंगे वन क्रांति

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के रूप में शुरू हुई जल क्रांति के बाद प्रदेश में वन क्रांति शुरू हो रही है। इसमें 60 लाख पौधे लगेंगे, लेकिन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी हर नागरिक की होगी। वह अगले साल पौधों की स्थिति देखेंगी।

उन्होंने कहा कि हमें अपने आचरण में लाना होगा कि सभी के जन्मदिन पर पौधारोपण कर इस अभियान को आगे बढ़ाएं। जल स्वावलंबन अभियान से पहले जिन गांवों में वर्ष में एक ही फसल हो पाती थीं, अब दो फसलें होने लगी है।

पंच-सरपंचों के मामलों की जांच अधूरी

गांव की सरकार चलाने वाले पंच-सरपंचों के खिलाफ साढ़े नौ हजार से भी अधिक शिकायतों की जांच अभी पैडिंग है। इनमें सबसे अधिक मामले जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के हैं। इनमें आपराधिक प्रकरणों जैसे गलत तरीके से चुनाव लड़ने, फर्जीवाड़ा करने और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें हैं।

पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के अनुसार पंच-सरपंचों के खिलाफ सबसे अधिक आरोप पद का दुरुपयोग करने व वित्तीय अनियमितता बरतने से संबंधित हैं।

अवैध डिपॉजिट स्कीम तो होगी जेल

अगर कोई व्यक्ति अवैध डिपॉजिट स्कीम को प्रमोट करता है और उसके नाम पर लोगों से पैसे लेता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा लोगों से जितने पैसे जमा किए, उसका दोगुना जुर्माना भी हो सकता है।

वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग इसके लिए नया बिल तैयार कर रहा है। जल्दी ही इसे केबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसका नाम 'बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स' रखा गया है। वित्त विभाग संसद के मानसून सत्र में इसे पेश करेगा।

किसान पशुपालन पर भी ध्यान दें

कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसानों को कृषि के साथ उन्नत पशुपालन को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मांग की तुलना में दूध की कमी होती जा रही है।

प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने पशुओं की नस्ल सुधार, उपचार और आहार पर भी ध्यान देने के साथ ही देशी गौवंश को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने पशु चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे सरकार की ओर से चलाई जा रही पशुपालन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग करें।

कृषि सुधारों पर ध्यान दें राज्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे कृषि क्षेत्र सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करें और कृषि उपउत्पादों के साथ ही खाद्यान्न प्रोसेसिंग को अहमियत दें। इसके अलावा उन्होंने तकनीकी बदलावों पर भी पैनी नजर बनाए रखने की वकालत की।

उन्होंने नीति आयोग की पहल पर सहकारी संघवाद के ऐजेंडे के तहत राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485